28102015-ls-ngp-04.qxd 10/28/2015 12:08 PM Page 1

लोकमत समाचार
तमसो मा ज्योतिर्गमय

{ दुनिया में सबसे बड़ा अपराध अपनी संभावनाओं का विकास न करना है. ■ रोजर विलियम्स }

संपादकीय

बर्बर अपराध के लिए सजा का सुझाव सराहनीय

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि बच्चों से बलात्कार करने वालों को सजा के तौर पर नपुंसक बनाने के प्रस्ताव पर गौर किया जाए. एक तल्ख ऑर्डर में जस्टिस एन. किरुबाकरन ने कहा, ''हम आंखें मूंद कर चुपचाप बैठे नहीं रह सकते. पूरे देश में बच्चों के साथ गैंगरेप की खौफनाक वारदात हो रही हैं.'' नपुंसक करने का सुझाव बर्बर लग सकता है, लेकिन इस प्रकार के क्रूर अपराध ऐसी ही बर्बर सजाओं के लिए माहौल तैयार करते हैं. बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन परंपरागत कानून ऐसे मामलों में सकारात्मक परिणाम नहीं दे सके हैं. कोर्ट ने तमिलनाडु के 15 वर्षीय एक बच्चे के यौन शोषण के आरोपी एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा मामला रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया. यह कटु सत्य है कि 2012 में बने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) जैसे कड़े कानूनों के बावजूद बच्चों के साथ यौन अपराधों में बढ़ोत्तरी ही दिखाई पड़ रही है. साल 2012 में 38,172 मामले सामने आए. 2013 में इनकी तादाद 58,224 हो गई और 2014 में 89,423 मामले दर्ज किए गए. अदालत का मानना है कि बच्चों के बलात्कारियों को बधिया करने से जादुई नतीजे देखने को मिलेंगे. आम लोगों के साथ-साथ अब कोर्ट भी यह महसूस कर रहा है कि मौजूदा कानून सार्थक परिणाम देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राजधानी दिल्ली में पिछले सप्ताह दो बच्चियों से गैंगरेप के मामलों को भी संज्ञान में लिया. हाईकोर्ट के जज ने ऐसे मामलों को 'खून जमा देने वाला' करार देते हुए कहा कि ऐसे क्रूर अपराधियों के लिए बधिया किया जाना ही एक सजा हो सकती है. आंकड़े बताते हैं कि बच्चों से रेप करने के मामलों में सिर्फ 2.4 प्रतिशत लोग ही दोषी ठहराए जाते हैं. बिगड़ते हालात के मद्देनजर कानून का खौफ कायम होना जरूरी है. अक्सर हम मध्य-पूर्व के देशों के 'आंख के बदले आंख' कानून की आलोचना करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वहां अपराधों की दर अन्य देशों के मुकाबले बेहद कम है. जाहिर है, वहां लोगों में कानून का खौफ कायम है. रूस, पोलैंड और अमेरिका के नौ राज्यों सहित दक्षिण कोरिया में भी ऐसे अपराधियों को बधिया करने का प्रावधान है. अनुभव में आया है कि हमारे देश में जब भी कड़े कानून की बात की जाती है तो कुछ लोग 'मानवाधिकार' का मुद्दा उठाने लग जाते हैं. किसी के मानवाधिकार का हनन करने वाले अपराधी के हक में मानवाधिकार की दुहाई देना अब बंद करना होगा. कई बार कानून के सख्ती से पेश आने में आधी-अधूरी पुलिस कार्रवाई और कानूनी पेचीदगियां भी आड़े आती हैं. मद्रास हाईकोर्ट का सुझाव सराहनीय है. सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. ■■

दूरदृष्टि

नेताजी के भाषण में झूठे आश्वासनों की भरमार से क्रुद्ध एक युवक सभा समाप्त होते ही मंच पर जा पहुंचा तथा एक झन्नाटेदार चांटा नेताजी के गाल पर रसीद कर दिया. वहां उपस्थित नेताजी के चमचों ने युवक की पिटाई आरंभ कर दी. तभी नेताओं ने उसे बचाया तथा नाराजगी का कारण जानना चाहा.

लघुकथा

मनोज सेवतकर

युवक ने आग्नेय नेत्रों से देखते हुए नेताजी से पूछा, ''आप जो कुछ बोल रहे हैं, सब झूठ है. यह बताइए, आप मुझ जैसे युवा बेरोजगारों के लिए केवल झूठे आश्वासन देने के अलावा और क्या कर रहे हैं?''

''अरे भाई, शांत हो जाओ. हमारे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम औरों की चिंता क्यों करते हो? तुम आज से हमारी सिक्योरिटी फोर्स में शामिल हो जाओ और मुंहमांगी पगार पाओ.''

युवक ने स्वीकृति दे दी और विदा ली.

इनके इस व्यवहार से नाराज होकर उनके प्रमुख पी.ए. ने प्रश्न किया, ''सर! इस नौजवान ने इतनी बदतमीजी की और आपने उसे अपने सिक्योरिटी फोर्स में शामिल कर लिया?''

''तुम भी एकदम बुद्धू हो. अरे, जो लड़का मुझे भरी सभा में चांटा मारकर अपने साहस का परिचय दे सकता है, वफादार जानवर बनने पर वह क्या कुछ नहीं कर सकेगा?'' नेताजी ने दूरदृष्टि का नक्शा पी.ए. के सामने रखा और पी.ए. नेताजी के दूरदृष्टि सूत्र को समझकर उनके पैरों पर झुक गया. ■■

अफ्रीका से संबंधों का नया अध्याय

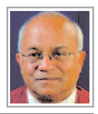

वेद प्रताप वैदिक
वरिष्ठ पत्रकार

आजकल नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन हो रहा है. आशा है कि विदेश नीति के क्षेत्र में भाजपा सरकार की यह सबसे सार्थक पहल सिद्ध होगी. 2008 और 2011 में भी इसी तरह के दो सम्मेलन हो चुके हैं लेकिन 54 देशोंवाले अफ्रीका के मुश्किल से दर्जन भर देशों ने भाग लिया था. इस बार लगभग सभी अफ्रीकी देशों के नेता भारत आ रहे हैं. कोई आश्चर्य नहीं कि यह अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा सम्मेलन सिद्ध हो. चीन और जापान के सम्मेलनों से भी बड़ा.

भारत और अफ्रीका के संबंध जितने प्राचीन और घनिष्ठ रहे हैं, दुनिया की किसी भी महाशक्ति के नहीं रहे. यह ठीक है कि कुछ यूरोपीय राष्ट्रों ने कई अफ्रीकी देशों को अपना गुलाम बना रखा था लेकिन भारत को श्रेय है कि उनकी आजादी का वह डटकर समर्थन करता रहा. गुट-निरपेक्ष आंदोलन में भी जवाहरलाल नेहरू ने कई अफ्रीकी नेताओं को काफी आगे बढ़ाया. इसके बावजूद कि भारतीय मूल के लाखों लोग अफ्रीका में पिछले सौ-डेढ़-सौ वर्ष से रह रहे हैं, अफ्रीका के साथ भारत के सामरिक और आर्थिक संबंध उल्लेखनीय नहीं रहे. इसके कई कारण रहे. एक तो भारत के नेताओं की दिमागी गुलामी. उन्होंने अपना ज्यादा ध्यान विश्वयारी में खपाया. अफ्रीकी नेताओं का वे सिर्फ सीमित इस्तेमाल करते रहे. दूसरा, भारत खुद इतना पिछड़ा था कि वह अफ्रीका में ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता था. तीसरा, कुछ अफ्रीकी देश या तो महाशक्तियों के बगलबच्चे बन हुए थे, कुछ में तख्ता-पलट होते रहते थे, कुछ गृह-युद्ध की चपेट में रहते थे और कुछ राष्ट्र 20वीं सदी में होते हुए भी 15 वीं सदी में रहते थे. अफ्रीका को 'अंधकार द्वीप' माना जाता था.

लेकिन पिछले दस-पंद्रह वर्षों में अफ्रीका का नक्शा बदला है. अब फौजी तख्ता-पलट की घटनाएं काफी कम हो गई हैं. गृहयुद्ध अभी चल रहे हैं लेकिन इक्के-दुक्के देशों में. अनेक देशों, खासकर पश्चिमी अफ्रीकी देशों की अर्थ-व्यवस्थाएं काफी तेज प्रगति के संकेत दे रही हैं. इसी का फायदा उठाने के लिए चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश अपने-अपने यहां बड़े अफ्रीकी शिखर सम्मेलन बुला रहे हैं. भारत का प्रयास भी है कि वह अफ्रीका से अपने आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए. लेकिन अभी उसके 54 देशों में से सिर्फ 29 देशों से ही राजनयिक संबंध हैं. 15-20 साल पहले तक भारत और अफ्रीकी देशों का व्यापार सिर्फ तीन-चार अरब डॉलर का था लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने पहल की और आज यह 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. जरा इसकी चीन से तुलना करें. उसका व्यापार 200 अरब डॉलर का है. इस साल के अंत तक भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की आशा है. भारत में अफ्रीकी पूंजी निवेश लगभग 65 अरब डॉलर माना जाता है लेकिन यह पैसा मॉरिशस आदि के जरिए आया हुआ है. इसका चरित्र क्या है और यह किसका है, यह कहने की जरूरत नहीं है.

अफ्रीका से निकाले गए कच्चे माल से भारत खुद को विश्व की महाशक्ति बना सकता है. भारत में बनी सस्ती और बढ़िया चीजों से वह अफ्रीकी बाजारों को पाट सकता है.

भारत के मुकाबले चीन अफ्रीका में छाया हुआ है. वह जितना माल अफ्रीका से आयात करता है, उससे चौगुना निर्यात करता है जबकि भारत तेल के आयात से ही दबा जा रहा है. भारत की कई गैर-सरकारी कंपनियों ने मिलकर लगभग 35 अरब डॉलर की पूंजी वहां लगा रखी है. वे लोकप्रिय भी हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं. आशा है कि सम्मेलन के बाद उनके काम में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी. भारत का ज्यादातर व्यापार सिर्फ पांच-छह अफ्रीकी देशों से ही होता है, जैसा दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, नाइजीरिया, अंगोला, मिस्र और अल्जीरिया आदि से. इसे फैलाने की जरूरत है.

अफ्रीकी महाद्वीप समृद्धियों का खजाना है. 54 देशों की कुल जनसंख्या भारत से भी कम है यानी सवा करोड़ भी नहीं जबकि उसकी जमीन भारत से कई गुना बड़ी है. एक अफ्रीका में कई भारत समा सकते हैं. वह अकेला अमेरिका, भारत, चीन और कई छोटे-मोटे देशों को मिला देने पर भी उनसे बड़ा है. अफ्रीका की तीन करोड़ वर्ग कि.मी. में फैली सोने, लोहे, तांबे, एल्युमीनियम, तेल और गैस की खदानें उसे विश्व का सबसे बड़ा शक्ति-केंद्र बनाती हैं. अफ्रीका से निकाले गए कच्चे माल से भारत खुद को विश्व की महाशक्ति बना सकता है. भारत में बनी सस्ती और बढ़िया चीजों से वह अफ्रीकी बाजारों को पाट सकता है.

अफ्रीका तक पहुंचने के लिए उसे किन्हीं अड़ंगों का भी सामना नहीं करना पड़ता है. सीधा समुद्री मार्ग उसे उपलब्ध है. चीन ने समुद्री मार्ग का लाभ उठाकर कई अफ्रीकी देशों से अपनी सामरिक घनिष्ठता भी बढ़ाई है. कई देशों में उसकी फौजी टुकड़ियां भी तैनात हैं और कुछ देशों में वह सामरिक अड्डे भी बना रहा है. हिंद महासागर से लगे हुए अफ्रीकी देशों की तरफ हमारी सरकार ने थोड़ा ध्यान जरूर दिया है लेकिन इस संपूर्ण महाद्वीप में भारत की सामरिक उपस्थिति बढ़नी चाहिए. वह आतंकवाद को भी रोकने में सहायक होगी.

अफ्रीकी देशों में भारतीय लोकतंत्र की विशेष साख है. लगभग हर अफ्रीकी देश से भारत के राजनयिक संबंध तुरंत स्थापित होने चाहिए. 40 हजार छात्रवृत्तियां हमने अफ्रीका छात्रों को दे रखी हैं. अफ्रीकी लोगों को हिंदी सिखाने और भारत-यात्रा के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए. गांधीजी का अफ्रीका-प्रवास दोनों क्षेत्रों को मानसिक रूप से भी जोड़ता है. यह सम्मेलन भारत-अफ्रीका संबंधों का नया अध्याय शुरू करेगा. ■■

टैगोर के आंगन में क्रांति और राजनीति

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

रवींद्र भवन दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है. स्वाभाविक है - रवींद्रनाथ टैगोर ने कला, साहित्य, संगीत, नाटक के क्षेत्र में भारत को अमूल्य धरोहर सौंपी. कला, संगीत, नाटक के साथ यहीं साहित्य अकादमी है. लगभग 45 वर्षों से इस अकादमी और रवींद्र भवन में पढ़ने, लिखने, सुनने, इंटरव्यू करने के अवसर मुझे मिले हैं. यदा-कदा सत्ता की राजनीति अथवा साहित्यकारों-कलाकारों की खींचातानी समर्थन-असहमतियों की बातें भी देखने-सुनने को मिलीं. लेकिन इस बार सचमुच साहित्य अकादमी ने स्वयं क्रांतिकारी इतिहास बना दिया. यह बात अवश्य कही जा सकती है कि अकादमी ने साहसिक अध्याय लिखने में थोड़ी देरी की. इससे पहले लेखकों पर हिंसक हमलों से दुःखी अकादमी से पुरस्कृत 42 लेखकों के आक्रोश और पुरस्कार लौटाने की घोषणाओं से संस्था की गरिमा पर प्रश्न उठने लगे. दुःखद पहलू यह है कि लेखकों के पुरस्कार लौटाने का विषय घृणित राजनीति का मुद्दा बन गया. यही नहीं भाजपा-संघ समर्थक तत्वों ने 'रवींद्र भवन' के पवित्र आंगन में 'राष्ट्रवादी' और 'राष्ट्रविरोधी' के बैनर लगाकर राजनीतिक कीचड़ से गंदा कर दिया. प्रगतिशील, समाजवादी, वामपंथी, कम्युनिस्ट अथवा कांग्रेस की विचारधाराओं से प्रभावित लेखकों का वर्चस्व निश्चित रूप से भारतीय साहित्य, पत्रकारिता, कला पर रहा है. आखिरकार, स्वतंत्रता आंदोलन का असर सब पर था और आजादी से पहले लोकमान्य तिलक ने गीता के मराठी-अनुवाद विश्लेषण के बावजूद किसी प्रगतिशील लेखक की भर्त्सना नहीं की थी. महात्मा गांधी महान धर्मनिरपेक्ष विचारों के बावजूद हिंदू सभाइयों, मुस्लिम लीगियों और संघ के प्रचारकों से भी संवाद में कोई संकोच नहीं कर सकते थे. प्रेमचंद, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर ही नहीं मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगू के पचासों लेखकों-पत्रकारों पर कट्टरपंथी विचारों अथवा सत्ता के दबावों का असर नहीं रहा.

बहरहाल, 1952 में स्थापित और 1954 में बाकायदा भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में प्रारंभ हुई अकादमी ने आजादी के समर्थन के साथ लेखन के विरुद्ध हिंसक हमलों और सामाजिक असहिष्णुता की भर्त्सना की. इस दृष्टि से अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और अकादमी के कार्यकारी मंडल के साहसिक प्रस्ताव का अभिनंदन होना चाहिए. परिषद ने सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कन्नड़ लेखक कलबुर्गी तथा अन्य बुद्धिजीवियों-विचारकों की सांप्रदायिक तत्वों द्वारा नृशंस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया.

अकादमी के इस प्रस्ताव से यह धारणा भी तथ्यहीन साबित हुई कि कलबुर्गी जी की हत्या पर संस्था मौन रही

टैगोर के आंगन को भविष्य में राजनीतिक कीचड़ से बचाने की जिम्मेदारी सबकी है.

थी. असलियत यह है कि हत्या के बाद अकादमी के अध्यक्ष तिवारी ने उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार से चर्चा करके कलबुर्गी परिवार से संपर्क कर संवेदना व्यक्त करने को कहा. फिर अकादमी के उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र के लेखकों ने सार्वजनिक सभा कर-के हत्या की निंदा की तथा जांच के साथ परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी.

विडंबना यह है कि संचार-क्रांति के बावजूद अकादमी तथा भारत के बड़े लेखक समुदाय के बीच संपर्क संवाद पर्याप्त नहीं हुआ. इस बीच विवाद गंभीर हो गया. देश के संस्कृति मंत्री और भाजपा के कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया. अब अकादमी ने पुनः लेखकों से अपील की है कि वे पुरस्कार लौटाने के कदम वापस ले लें, क्योंकि अकादमी लेखकों की स्वायत्त संस्था है.

लेकिन यह खबर चिंताजनक है कि अब भाजपा-संघ समर्थक संगठन इन लेखकों के विरुद्ध प्रदेशों में अभियान चलाएंगे. टैगोर के आंगन को भविष्य में राजनीतिक कीचड़ से बचाने की जिम्मेदारी सबकी है. ■■

ब्रिक्स बैंक की कठिन है राह

भरत झुनझुनवाला
आर्थिक विश्लेषक

'ब्रिक्स' देशों में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका आते हैं. इन देशों ने बीते समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है. इसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता है. इस बैंक को अधिक पूंजी चीन द्वारा उपलब्ध

विश्व बैंक द्वारा स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मॉडल को ब्रिक्स बैंक लागू करना चाहता है.

कराई जाएगी. इस बैंक द्वारा इन पांच देशों को बुनियादी संरचना के विकास के लिए लोन दिए जाएंगे. इस बैंक की स्थापना करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित को बढ़ाया जा रहा था. ब्रिक्स बैंक का लक्ष्य होना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छोड़कर विकास का दूसरा मॉडल स्थापित करे. लेकिन ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष ने हाल में मुंबई में स्पष्ट किया है कि ब्रिक्स बैंक का उद्देश्य विश्व बैंक का विरोध करना नहीं है बल्कि वे विश्व बैंक की मदद चाहते हैं. यानी विकास के नए मॉडल को स्थापित करने के स्थान पर विश्व बैंक के मॉडल को ही लागू करना चाहते हैं. अंग्रेजों द्वारा लागू आईएएस व्यवस्था को स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपनाया. गांधीजी द्वारा सुझाए गए गरीबोन्मुख विकास के मॉडल को त्याग कर इन अधिकारियों ने उसी सरकारवादी व्यवस्था को लागू किया जिसके विरोध में हमने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा था. अंग्रेजी सरकार के स्थान पर भारतीय सरकार स्थापित हो गई. आम आदमी के लिए कोई अंतर नहीं पड़ा. इसी प्रकार विश्व बैंक द्वारा स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मॉडल को ब्रिक्स बैंक लागू करना चाहता है. गरीबोन्मुख मॉडल को त्याग कर ब्रिक्स बैंक द्वारा उसी बहुराष्ट्रीय कंपनी आधारित विकास के मॉडल को प्रवर्तित किया जाएगा जिसके विरोध में इस बैंक की स्थापना की गई है.

ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय चीन की वाणिज्यिक राजधानी शंघाई में स्थापित किया गया है. बैंक के प्रथम प्रमुख भारत के जाने माने बैंकर के. वी. कामथ को नियुक्त किया गया है. अब तक विश्व अर्थव्यवस्था का वित्तीय संचालन अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता रहा है. इन दोनों संस्थाओं की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स नामक शहर में की गई थी इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कहा जाता है.

कामत के सामने कठिन चुनौती है कि ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का अंधानुकरण करने के स्थान पर नई दिशा बनाएं. ऐसी विश्व रचना की ओर बढ़ें जिसमें ब्रिक्स देशों में रहने वाले 42 प्रतिशत लोगों द्वारा विश्व के 42 प्रतिशत प्राकृतिक संसाधनों की खपत की जा सके. ■■

नजर के पार

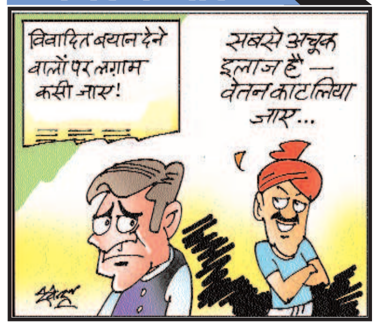

अंडरवर्ल्ड की बड़ी कहानी है छोटा राजन

लोकमित्र
जाने-माने पत्रकार

शेक्सपीयर ने सही कहा था, नाम में क्या रखा है? इसलिए छोटा राजन नाम में जुड़े 'छोटा' शब्द पर न जाइए. छोटा राजन अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम, एक बड़ी कहानी है. वह भारत के सर्वाधिक वांछित गैंगस्टरों में से एक है. नतीजतन इंटरपोल द्वारा जारी रेडकॉर्नर नोटिस के आधार पर इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के संयुक्त पुलिस दल द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाना सबके लिए एक बड़ी कामयाबी है. लगभग 55 वर्ष का राजेंद्र सदाशिव निखालजे उर्फ मोहन कुमार उर्फ छोटा राजन सिडनी से तीन घंटे की उड़ान के जरिए इंडोनेशिया के बाली द्वीप पहुंचा था.

गौरतलब है कि सीबीआई ने मुंबई पुलिस के अनुरोध पर जुलाई, 1995 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. वह मोहन कुमार नाम के पासपोर्ट पर बाली पहुंचा था. 25 अक्तूबर, 2015 को उसे बाली के एगुराहारी एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन और पासपोर्ट चेकिंग के दौरान स्थानीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया. इंडोनेशिया इंटरपोल को कैनबरा इंटरपोल से रेडकार्नर नोटिस जारी किया गया था. कैनबरा इंटरपोल ने इंडोनेशिया इंटरपोल को बताया था कि वह पासपोर्ट नंबर जी-9293860 से सुबह 10 बजे इंडोनेशिया की गरुडा एयरलाइंस की उड़ान संख्या जीए 715 के जरिए बाली के डेनपसार पहुंचने वाला है. माना जा रहा है कि पिछले पंद्रह दिनों से वह इंटरपोल के रडार में था. मालूम हो कि छोटा राजन पिछले सात साल से आस्ट्रेलिया में छिपा हुआ था.

छोटा राजन भारत की टॉप 10 वांटेड सूची का एक अहम हिस्सा है. हिंदुस्तान में उसके खिलाफ 12 अक्तूबर 1994 को अरेस्ट वारंट और 9 जुलाई 1995 को छवण-360/7-1995 से रेडकार्नर नोटिस जारी किया गया था. राजन पर भारत में 15 से 20 लोगों के मर्डर का आरोप है. इसके अलावा उस पर तमाम फिरौती के भी मामले हैं. राजन भले पिछले कई सालों से भारत में न हो लेकिन उसका यहां आज भी नेटवर्क मजबूत है. आखिर इसी नेटवर्क और कमाई के जरिए वह सालों से विदेशों में ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था. शायद उसका अपना एक राजनीतिक स्पेस भी है.

सवाल है क्या यह सब मिलीभगत का खेल है? अगर सूत्रों की मानें तो एक योजना के तहत राजन ने मुंबई स्थित अपने सोर्स को अपनी ट्रैवेल्स डिटेल बताई जो सर्विलांस के जरिए पुलिस और फिर इंटरपोल तक पहुंची. इस तरह वह अपनी ही चाल के जरिए जाल फैलाकर खुद को गिरफ्तार करवाया. ऐसा हो भी सकता है क्योंकि एक और संयोग इस कहानी की तरफ इशारा कर रहा है. लगता है इस गिरफ्तारी को लेकर सरकार को पहले ही से पता था. कम से कम मुख्य जानकारी तो थी, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो विदेश राज्यमंत्री वी. के. सिंह इंडोनेशिया में पहले से ही मौजूद न होते.

बहरहाल कुछ भी हो, राजन को यहां लाने से पुलिस को उससे दाऊद के बारे में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं. सिर्फ दाऊद के बारे में ही नहीं उसके कई दाएं बाएं हाथों के बारे में ऐसी जानकारियां मिल सकेंगी.

तोल बोल

शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार में है लेकिन सरकार हमारी नहीं है. नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल रहे महत्वपूर्ण विभाग शिवसेना के पास नहीं हैं.

■ संजय राऊत, शिवसेना नेता

सूखा अदृश्य त्रासदी है. भूकंप आता है तो नजर आता है और उससे छोटे-बड़े, अमीर-गरीब सभी प्रभावित होते हैं. अकाल दबे पांव आता है और गरीब पर चोट करता है.

■ योगेंद्र यादव, पूर्व नेता 'आप'

© लोकमत समाचार ... बालाजी मुले ... 192, 207, 208 ...
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
0712-2423527 (7 ...) ... 6618555
Email : lsedit.ngp@lokmat.com
advt.ngp@lokmat.com circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 28 अक्तूबर

आज ही के दिन 1962 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने मास्को के सरकारी रेडियो से घोषणा की थी कि उनका देश अमेरिका के निशाने पर सधी, क्यूबा में तैनात परमाणु मिसाइलें हटा लेगा. उनकी इस घोषणा के साथ दुनिया ने राहत की सांस ली, वरना ऐसा लग रहा था कि शीत युद्ध के जमाने की महाशक्तियां दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ खींच ले जाएंगी.

सोवियत नेता की इस घोषणा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस कदम का स्वागत किया. कैनेडी ने इस बात का भी वायदा किया कि अमेरिका बदले में वामपंथी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा साथ ही क्यूबा के चारों तरफ की गई अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी भी उठा ली जाएगी. ■■

- 1867-स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का आयरलैंड में जन्म.
- 1891-जापान में आए भूकंप से 7300 लोग मरे.
- 1918-आस्ट्रिया और हंगरी के अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र हुआ.
- 1955-मिस्र और सऊदी अरब ने रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए.
- 2009-पाकिस्तान के पेशावर में बम धमाके से 117 मरे, 213 घायल।
- 2012-सीरिया में संघर्ष विराम टूटने के बाद 128 लोग मारे गए.

पाठकों के पत्र

बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं

इन दिनों युवाओं द्वारा तूफानी गति से वाहन चलाए जाने के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. युवा बिना 'होश' के 'जोश' में बेतहाशा गाड़ियां भगाते हैं, जिससे पैदल चलने वालों और रास्ते से गुजरने वाले बुजुर्गों को भी जान का खतरा बना रहता है. अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में गाड़ियां न थमाएं और युवाओं को समझाएं कि इस तरह जोश में होश खोना ठीक नहीं है. तभी बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है.

■ पी.बी. पराडकर 'ललित', छिंदवाड़ा

बढ़ती सांप्रदायिकता

देश में सांप्रदायिक हत्याएं सुनियोजित षड़यंत्र के तहत होती दिखाई देती हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें राजनीतिक रंग क्यों दिया जाता. देश में अब दंगे, हत्याएं ही वर्तमान और भविष्य बनते दिखाई दे रहे हैं. देश की एकता, अखंडता के लिए द्वेषपूर्ण भावनाओं और भड़काऊ भाषणों का अंत किया जाना चाहिए, तभी हमारे देश में अमन और शांति बनी रह सकती है.

■ मलिक, नागपुर

जिगर का बटुआ

एक बार उर्दू के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का बटुआ गुम हो गया. काफी पैसे थे उसमें. जानकारी मिलने पर एक दोस्त बटुए का अफसोस जताने आए. पूछने लगे कि यह कैसे हुआ.

प्रसंग

जिगर साहब ने उन्हें बताया, ''कल एक साहब से चलते-चलते मुलाकात हुई थी. काफी गर्मजोशी से मिले थे. मैंने सोचा कोई मिलने वाला होगा. तांगे में बैठकर जब घर आ रहे थे तो इन साहब ने मेरी जेब से कुछ निकाला. पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर मैंने अपना बटुआ उनके पास देख भी लिया. लेकिन उससे कुछ कहा नहीं.''

दोस्त को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ. उन्होंने इसका कारण पूछा.

जिगर साहब बोले, ''अगर मैं उनसे कहता कि आपने मेरा बटुआ चुराया है तो उस वक्त उन्हें जो परेशानी होती, वह मुझसे देखी न जाती.'' ■■